



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

सेवा में

1. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
2. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: एम.पी.-1/2/2022/3791

दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

विषय:- रबी तथा खरीफ वर्ष 2022-23 की फसलों की हैण्डलिंग के लिए (ई-टैण्डरिंग के माध्यम से) श्रम व दुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति करने बारे पोलिसी।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

1. रबी तथा खरीफ वर्ष 2021-22 की फसलों की हैण्डलिंग के लिए नियुक्त किये गये श्रम व दुलाई ठेकेदारों की कार्य अवधि दिनांक 31.3.2022 को समाप्त होने जा रही है। इसलिए हरियाणा राज्य की सभी मण्डियों में रबी तथा खरीफ वर्ष 2022-23 की फसलों की हैण्डलिंग के लिए नये सिरे से श्रम व दुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति ई-टैण्डरिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है जिसकी कार्यवाही शीघ्र की जानी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में टैण्डरदाताओं से अपने-2 जिले में ऑन लाईन टैण्डर आमंत्रित करने के लिए "टैण्डर नोटिस" समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु जिला स्तर पर खुला प्रचार किया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर खुला प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों जैसे कि सभी खरीद एजेंसियों, मार्केट कमेटी, Municipal Committee, पंचायत घरो व खरीद केंद्रों आदि के नोटिस बोर्डों पर टैण्डर नोटिस को चस्पा करें। जिलावार टैण्डर आमंत्रित करने के लिए टैण्डर नोटिस की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।
2. विषयाधीन टैण्डर के माध्यम से नियुक्त किये गये श्रम व दुलाई ठेकेदारों द्वारा खरीद किये गये खाद्यान्नों के उठान हेतु पर्याप्त लेबर व इसको मण्डी स्थल से 8 किलोमीटर तक के दायरे में स्थित भण्डारण स्थलों तक पहुंचाने हेतु परिवहन कार्य श्रम व दुलाई ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर स्थित भण्डारण/प्रेषण हेतु परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदारों द्वारा किया जाना है, जिनके लिए अलग से टैण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं।
3. श्रम व दुलाई ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य की खरीद एजेंसीवार/जिलावार/मण्डीवार, संयुक्त टैण्डर आमंत्रित करने तथा इनके अन्तीकरण के लिए जिला टैण्डर कमेटीयों का गठन भी पूर्व वर्षों की तरह निम्न प्रकार से किया गया है तथा कमेटी का कार्य टैण्डर की शर्तों में व्याखित किया हुआ है:-

क्र०	पदनाम	पद
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक या उन द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
3	उप मण्डल अधिकारी (ना०), जिला मुख्यालय	सदस्य
4	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक,	सदस्य सचिव
5	भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य की सभी खरीद एजेंसीयों के जिला प्रबन्धक	सदस्य

4. वर्ष 2022-23 की रबी तथा खरीफ की फसलों की हैण्डलिंग के श्रम व दुलाई कार्यों के बेसिक दरों (एस.ओ.आर) का विवरण अनुबन्ध 'ए' में संलग्न है। इस अनुबन्ध के भाग-1 के

1/4



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

2-

श्रम व दुलाई कार्य व इनके दर मार्किट बाई लॉज अनुसार मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अलग से निर्धारित किये हुए हैं। इसलिये इन मदों के दर टैण्डरों के माध्यम से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुबन्ध-ए के भाग-2 के श्रम व दुलाई कार्यों के बेसिक दरों पर टैण्डरों के माध्यम से दर मांगे जाने हैं तथा टैण्डरदाताओं द्वारा भाग-2 के श्रम व दुलाई कार्यों के बेसिक दरों पर अपने दर quote किये जाने हैं।

5. वर्ष 2022-23 के लिए नियुक्त किये जाने वाले श्रम व दुलाई ठेकेदारों की नियुक्तियों वारे टैण्डर की शर्तों एवं इकरारनामे का प्रारूप साथ संलग्न किया जा रहा है। टैण्डर की शर्तों में उक्त व्याखित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य तथ्य, जिन के अनुसार टैण्डर आमंत्रण तथा उन का अन्तीकरण किया जाना है, विस्तृत रूप से व्याखित किये गये हैं। अतः टैण्डर कमेटी, "टैण्डर आमंत्रण एवं उन का अन्तीकरण" टैण्डर की शर्तों अनुसार करने की कार्यवाही करे जोकि टैण्डर प्रक्रिया का ही भाग होगा। सभी जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले नियंत्रक यह भी सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों से टैण्डर की शर्तों अनुसार इकरारनामा (on proper stamp paper) किया गया हो तथा उन द्वारा हस्ताक्षरित (प्रत्येक पृष्ठ) टैण्डर की शर्तें, इकरारनामे के साथ रखी गई हों।

6. वर्ष 2022-23 हेतु श्रम व दुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए कुछ pre-qualification conditions निर्धारित की गई हैं जो की संलग्न "Terms and Conditions" में उल्लेखित की गई हैं।

7. वर्ष 2022-23 में श्रम ठेकेदार के द्वारा खाद्यान्नों की दुलाई का कार्य केवल परिवहन के अधिकृत माध्यम/साधन द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जारी हिदायतों/नियमों अनुसार किया जायेगा।

8. वर्ष 2022-23 के दौरान खरीद की गई फसल को मण्डी से ट्रको में लदाई करके गोदामों/राईस मिल में भण्डारण से पूर्व प्रत्येक ट्रक की तुलाई सम्बन्धित जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकृत उचित धर्मकांटे पर करवानी आवश्यक होगी। खरीद की गई फसल के तोल की समानता व सहीपन की सुनिश्चितता के लिए जिला नियन्त्रकों को अधिकृत किया जाता है कि वे धर्मकांटों की सूची मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा सम्बन्धित निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान से प्राप्त करें व List पर सम्बन्धित उपायुक्त की prior approval लेकर स्वीकृतियां जारी करें जिन पर खरीद की गयी गेहूं की तुलवाई करवाई जानी है।

9. रबी तथा खरीफ खरीद सीजन 2022-23 के दौरान फसल की खरीद के 24 घण्टे के अंदर आढती को फसल का उठान के लिए ऑफर करना है।

10. श्रम व दुलाई ठेकेदार समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे तो उन पर पेनेल्टी लगाई जाएगी। यदि परिवहन ठेकेदार 3 घण्टे की समय सीमा में ट्रक उपलब्ध नहीं करवाएगा तो उस पर पेनेल्टी लगेगी। यह सारी प्रक्रिया ई-खरीद पोर्टल पर रिकार्ड की जाएगी।

11. वर्ष 2022-23 हेतु श्रम व दुलाई परिवहन दरों की स्वीकृतियों को जारी करने के लिए पृष्ठांकन क्रमांक एस.ओ.एम.पी.-1-2006/5739 दिनांक 31.3.2006 द्वारा सभी उपायुक्तों को निम्न शक्तियां delegate की गई हैं:-

Sr. No. of Appendix-I (Part-A) of PR A/cs Manual Part-I	Nature of powers	To whom delegated	Extent
9	To sanction	Deputy	Full powers subject to the



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

3

	proforma of mandi charges	Commissioner of the concerned District/ Additional Director/Joint Director/Deputy Director Food Civil Supplies & Consumers Affairs Haryana.	following conditions:- (i) The rates are settled by inviting tender by the Tender Committee as per policy on the subject. (ii) The rates are competitive and reasonable.
25	To sanction transport charges in respect of foodgrains, coarsegrain/oilseeds and stock articles transferred from one place to another and approval of contracts with the transport companies regarding the rates from road transport.	Deputy Commissioner of the concerned District/Additional Director Food Civil Supplies & Consumers Affairs Haryana.	Full powers subject to the following conditions:- (i) The rates are settled by inviting tenders by the Tender Committee as per policy on the subject. (ii) The rates are competitive and reasonable. (iii) The payment is made on per quintal per kilometer basis.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार केन्द्र वार श्रम एवं ढुलाई की दरों की स्वीकृतियां सम्बन्धित जिला उपायुक्त के अनुमोदन उपरान्त जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और तत्पश्चात् मुख्यालय को इस स्वीकृति की प्रति/आवश्यक सुझाव (यदि कोई हो) भिजवाना सुनिश्चित करें। कृपया इसे परम अग्रता प्रदान करें।

Megh
 7/03/22
 उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति
 तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/2/2022/3792

दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति जनरल मैनेजर भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रिय कार्यालय पंचकुला, प्रबन्ध निदेशक, एच.डब्ल्यू.सी, हैफेड तथा मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वर्ष 2022-23 की रबी तथा खरीफ की फसलों की हैण्डलिंग के श्रम कार्यों के ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिये तैयार की गई टेंडर की शर्तें एवं इकरारनामे के प्रारूप की प्रति भी सूचनार्थ संलग्न है।

Megh
 07/03/22
 उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति
 तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

- 4 -

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/2/2022/3793

दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, करनाल एवं गुड़गांव को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति
तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/2/2022/3794

दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. The State Informatics Officer, National Informatics Center, New Secretariat Haryana, Chandigarh.
2. Technical Director, NIC with the request to issue necessary directions to all the DIOs for smooth processing of online E-tenders in all the districts.

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति
तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/2/2022/3795

दिनांक चण्डीगढ़ 07.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को माननीय उप मुख्य मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं पूर्ति निदेशक (खाद्य) के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ पी.एस/माननीय उप मुख्य मंत्री एंवम खाद्य एवं पूर्ति मंत्री महोदय,
2. पी.एस/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं पूर्ति विभाग,
3. पी.एस./निदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग।

उप निदेशक

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति
तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

Terms and Conditions of Labour & Cartage Tenders Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana.

1. Contractor/Tenderer should not have been blacklisted by any of the Department/Semi Government Organisation of State Government and by FCI, and not connected to any firm who has been so blacklisted.
2. Submission of the e-Tender documents: The tenderer shall have to deposit an amount of Rs. 1000/-plus 18% GST i.e. totalling Rs. 1180/- e-tender fees which is non-refundable.
3. The tender shall start on at 5:00 PM and close on at 5:00PM.
4. Opening of e-tender: Technical bids shall be opened on at 2:00 PM and the financial bids of the tenderer who qualify in the Technical Bids be opened on at 04:00PM. These Bids shall be opened at respective district offices in the presence of the tenderer who may be present.
5. Tenderers should submit both the tender bids i.e. "Technical Bid" and "Financial Bid" only in Electronic form (Refer Tender documents). Financial Bid Proposal shall be submitted mandatorily online under commercial Envelope and original not to be submitted manually). Financial Bid only will be opened after complete Technical Bid.
6. Each Technical Bid must be accompanied by an earnest money i.e. 5% of the total cost of contract of previous year, of mandi for which tender is to be submitted through RTGS as per bank details given below:-

Name of beneficiary	District Food & Supplies Controller
Account No.	
Name of Bank	
IFSC Code	

7. Technical Bid not accompanied with the requisite amount of earnest money will be rejected. The amount of earnest money of the unsuccessful tenderer will be refunded within 5 working days from the date of tender except L2 & L3 who's EMD will be refunded within 15 working days from the date of finalisation by the tender.
8. The following documents are required with Technical bid:-
 - i) Certified copy of Partnership Deed/Registration of Firm.
 - ii) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
 - iii) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
 - iv) Solvency certificate issued by the banker.
 - v) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of the preceding three financial years.
 - vi) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value.
 - vii) Tenderer will submit a certificate of satisfactory work done during previous three years in the field of mandi labour and cartage work only from the concerned DFSC/DMs of the state procurement agencies & FCI having detail of volume of work done in the mandis. Out of these three years, the tenderer should have handled the work in any one year equivalent to work



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

- 2 -

to be allotted in the mandi for which he/she is submitting the tender. Further, the experience of individual partner of any partnership firm only will be considered for the experience required if it is equal to the required experience for that tender i.e. labour and construction societies work experience will not be considered.

- viii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender and for balance trucks he/she may have agreement with any transport company/truck owners with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ Rs 60,000/- per trucks of short no of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. The additional security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points. If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3, L-4, L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. The same will be applicable for all the tenderers. The requirements of trucks are as under:-

Class of Mandi	Arrival/Procurement	No. of Trucks required
A	Upto 10000 MT	10
B	From 10001 MT to 20000 MT	20
C	From 20001 MT to 40000 MT	30
D	From 40001 MT and above.	40

Note:-1) Price bid will be opened only if the tenderer qualifies in the technical bid.

Note:-2) Previous/Projected Procurement figures of Rabi & Kharif crops may be taken from the office of the DFSC/DM concerned of the agency in District.

9. Conditional tenders will not be entertained and shall summarily be rejected by the Distt. Tender Committee.
10. The Distt. Tender Committee reserves the right to negotiate with the valid tenderer (L-1) In cases, the Tender Committee considers that the negotiated rates are not reasonable/competitive/workable, the Committee may consider cancelling and re-inviting the tenders.
11. The District Tender Committee reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. After the final acceptance of the tender by the tender committee, no request for further increase of rate for any operation shall be entertained.
12. The successful tenderer shall deposit the amount of security i.e. 10% of the total cost of contract of previous year, within three working days of the acceptance of his tender by the Tender Committee. The security will be deposited in the office of the DFSC/DM concerned in the District. The earnest money deposited by successful tenderer shall be adjusted in the security amount.
13. The successful tenderer shall also execute an agreement on a stamp paper with the DFSC/DM concerned within 5 working days of the acceptance of his tender.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

3-

He/they shall also furnish two sureties each of equal amount of security, as above, from two reputed local persons/arhtias possessing sufficient immovable property. In case of his/their failure to do so the amount of earnest money shall stand forfeited and he/they will be black-listed and debarred for allotment of any work of the State Procurement Agencies along with FCI in future.

14. In case the lowest tenderer fails to deposit the requisite amount of security and fulfill requisite formalities as above, the DFSC/DM of the concerned agency will be competent to make an offer to the next lowest tenderer L2 & L3 with prior concurrence of the concerned Deputy Commissioner. In this regard the clauses are including:-
- (a) Earnest money of two other lowest bidders (L2 and L3) should not be returned for 15 days so that quotes of L2 and L3 can be considered in case of default of first tenderer (L1).
 - (b) Offers will be made to L2 to work at L1 rates in the eventuality of L1 not being able to work as per the terms and conditions of tenders. In case L2 is willing to work at L1 rates, he will be allotted the balance work. In case of unwillingness of L-2, offer will be made to L3 to work at L1 rates. In case L3 is willing, L3 will be allotted the work at L1 rates. Should L3 not be willing, then negotiation will be held with L2 and if the rates of L2 are unreasonable, the authorities will be free to make a counter offer to L2 and if this is not accepted, the discussions with L2 will be terminated and similar negotiations will be entered with L3. The authorities may quote a counter offer here also as in the earlier case if L3 rates are unreasonable or the subsequent rates quoted by L3 are felt to be unreasonable or high. In case there is no acceptance of counter offer or if the rates in negotiations are too high, the committee may cancel the tender. Fresh local tenders will be called, if necessary, giving 24 hours notice.
 - (c) However, any new contract, in case of any emergency will be awarded only after the emergency or urgency is properly justified by District Tender Committee headed by the Deputy Commissioner and approval of Director Food, Civil Supplies and Consumer Affairs is taken for this.
 - (d) There will be no earnest money requirement for new contracts in case the earlier contract is cancelled on the above account.
15. If the successful tenderer, after depositing security amount, resiles from his offer and does not come forward for entering into an agreement with the concerned Procurement Agency within the stipulated period, then his security amount shall stand forfeited and concerned Procurement Agency will be at liberty to get the work done at his risk and cost or do the agreement with L-2 at L-1 rates.
16. If the successful tenderer after depositing security amount and entering into an agreement with the concerned State Procurement Agency, fails to undertake the work or refuses to work or make default in proper fulfillment of the conditions of the Agreement, or leave the work in between, the security deposited by him shall stand forfeited and he will be black listed besides being debarred from allotment of any work of the State Procurement Agencies in future. In addition, the Department/Agency shall be competent to get the remaining work carried out on the prevailing market rates/ by appointing regular contractors at the risk and cost of the defaulting contractor, by serving him with one day's notice and in that case extra amount incurred by the Department/Agency shall be recoverable from the defaulting contractor from his security and pending bills. In case any amount still remains recoverable, that would be recovered from the two sureties given by the contractor. In case the recoverable amount from the defaulting contractor still



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

4 -

remains after the above adjustment, the exceeded amount shall be recovered from the defaulter contractor as arrears of land revenue.

17. Successful tenderer will have to start the work as and when asked by the DFSC/DM of the Agency and is required to provide sufficient labour and number of trucks as required by the Inspector-in-Charge/Purchaser of the centre, as per terms and conditions of the tender, within a time limit of 3 hours after the purchase. A copy of daily purchase figures (PR-54) will be communicated to the contractors on their registered e-mail IDs and they will be required to provide trucks accordingly and lift the stocks within 48 hours. In case the contractor fails to perform, Rs. 500/- per truck will be charged as penalty on the remaining stocks.
18. Contractor is also required to provide sufficient labour and transport food grains/coarse grains/stock articles from mandis/storage points as the case may be on the directions of the DFSC/DM of the concerned agencies. In addition he/she/they also will be responsible to compensate any loss caused to the Procurement Agencies for non delivery of stocks of food grains/coarse grains and stock articles at destination in time. Services of any other source will be utilized by the Department/Agency without issuing any notice to the labour and cartage contractor and payment of such operations carried out by such Company, will be made by the procuring Agency directly to that Company and the labour and cartage contractor shall have no objection or claim in this regard. By utilizing the services of such standby Company, the transport contractor will not be absolved of his liabilities/obligations under the risk and cost clause above for food grains lifted by engaging any other person/mode of conveyance. The extra expenditure payable by the procuring agency shall be recoverable from the defaulting labour and cartage contractor in due course and as per terms and conditions of risk and cost as specified above. If labour and trucks are not supplied as per demand, besides the penalty, the security amount may be forfeited. In such a case, a short notice will be issued to the defaulting labour and cartage contractor and in case of proven default/deficiency in service, the security deposited by him may be forfeited and he may be black listed besides being debarred from allotment of any work of the State Procurement Agencies in future.
19. The contractor shall arrange mechanized unloading of foodgrains at all storage points for the entire procurement in respect of mandies (Fatehabad, Barwala, Kaithal New, Karnal, Ellenabad & Sirsa) where arrival is more than 100000 MT.
20. The transporter should arrange GPS/VLTS (Vehicle Location and Tracking Device of AIS 140 standard as notified by MORTH) on all the trucks. These GPS/VLTS trackers may belong to any company. To monitor these GPS/VLTS, the services of a third party service provider will be taken. The geo fencing of truck route will allow to receive notification if the driver deviates from the planned path. The deviation will be sent to the transporter on e-mail and driver will tracked through his mobile phone.
21. The contractor shall have to execute all the work to the full satisfaction of the Department/Agency. Directions for proper execution of the contract or for speedy and careful handling of foodgrains and stock articles, issued in this behalf by DFSC/DM or his representative shall be binding on him.
22. The contractor shall ensure proper building of stacks having adequate alleyways in the godowns/CAP storage of the concerned Procurement Agency as per the instructions given by their Staff. He/they shall squarely be responsible for any type of shortages of bags found from within the stacks at any subsequent stage. He/they shall also ensure that the stacks built by his/their labour are stable and



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

5

do not tilt/fall. In case it happens, he/they shall be liable to get the same restacked at his/their own cost within 24 hours.

23. The contractor shall be liable to do the job of handling and local cartage work for the stocks/stock articles being received/sent from/to other centres. Contractor shall have no objection for utilizing the services of own vehicles by Government/Agencies/Societies of HAFED for procurement/lifting of stocks/stock articles.
24. The contractor will be governed by the laws of land for the time being in force in India.
25. The contractor shall comply with or cause to be complied with all the labour regulations enactments/laws made by the State Government and the Central Govt. from time to time in respect of payment of wages of the workers/labour and all related matters.
26. The contractor shall nominate/authorize in writing one or more responsible representatives who will act on his behalf in day-to-day working of the contract. The labour contractor or his representative shall contact to the office in-charge of the agency or any other officer/official acting on behalf of the agency and take instructions regarding the work to be carried out on a day-to-day basis.
27. The contractor shall take adequate steps and necessary precautions to avoid wastage and damage to the foodgrains during handling and transportation of stocks. The contractor shall be liable for any loss which the agency may suffer during handling and transportation of stocks. The contractor will be responsible for any kind of shortage of foodgrains/coarsgrains/stock articles in transit. He will also incur all charges related to labour and transportation, and toll tax etc.
28. The contractor will provide adequate number of stitchers and sweepers at his own cost at all loading/unloading and other operational points to carry out minor repairs with twine to the leakage of bags.
29. The contractor shall collect all sweepings and spillings of food-grains at all loading/unloading and other operational points and fill them after cleaning if necessary in slack bags or in other empty bags supplied by the agencies and firmly stitch them with at least 16 stitches. The twine/thread for this purpose shall be provided by the agencies.
30. Deduction of Income Tax and surcharge, if any, applicable shall be made at source as per law. It shall be the responsibility of the contractor to comply with the provisions of the Income Tax Act.
31. The security will be refunded only after the successful execution of the contract. The security will be refunded on completion of internal audit of accounts for that period and if nothing is found due against him.
32. All persons employed by the contractor shall be engaged by him as his own employees/workers in all respects and the responsibility under the Indian Factories Act or the Workmen's Compensation Act 1923 or Employees Provident Fund Act or any other similar enactments in respect of all such personnel/labour shall be only that of the contractor. The contractor shall be bound to indemnify the agency against all claims whatsoever in respect of the said personnel/labour under the Workmen's Compensation Act 1923 or any statutory modification thereof or otherwise in respect of any damage or compensation payable in consequence of any accident or injury sustained by any workmen or other person whether in employment of the contractor or not.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

6

33. The contractor shall be liable to provide the basic facilities such as health, ESI, and Compensation etc. as per exiting law to the labourers. The contractor shall be liable to deduct and deposit at source as per rules. Further the labour contractor will be bound to pay wages as per minimum Wages Act, fixed by the Competent Authority from time to time and shall furnish an affidavit to the concerned DFSC/DM of the Agencies concerned that the payment has actually been made to the labourers for the work done by them as per wages Act. Admissible overtime will also be payable as per rules. A monthly report of statutory compliance of will be given by the Contractor to DFSC/DMs concerned.
34. That the contractor will not claim for handling of foodgrains, pulses, mustard, bajra, coarsegrain and other article stocks in the godowns under FCI guarantee scheme.
35. In case it is considered by the procuring agency that the payment made to the contractor on tendered rate is higher than the market prevailing rates, the differential amount will be recovered from his pending claims/security or otherwise.
36. In case the stocks are stored/delivered to FCI other than the purchase centre/mandi and the cartage rates are higher than the local transportation union rates/rates fixed by the DC/Department, the payment shall be restricted as per local transportation rates/rates fixed by DC/Department.
37. The work of operations contained in the Part-I of Annexure-A i.e. filling, sewing, weighing, stitching (manual machine stitching), marking on bags, temporary stacking & loading of bags on to the trucks/trolley from mandi will be given to mandi arthia association as per rates fixed by the HSAMB. They will execute agreement with DFSC/DMs of concerned agency before the scheduled date of opening of tender by District Tender Committee.
38. In case any dispute arises between the contractor and the State Procurement Agencies, the matter will be referred to the Director Food Civil Supplies and Consumer Affairs/M.D. of the agency concerned or his nominee for adjudicating the matter of dispute under the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and his decision shall be binding on both the parties.
39. E-Tenderer may clearly mention his/her bank account no., name of bank and its branch along with IFSC code for refund of EMD and for labour and transportation payment in proforma 'x' given with technical bid value as per notification issued by concerned State Govt. from time to time.

Megh
7/3/22
Deputy Director

for Director General Food, Civil Supplies and
Consumer Affairs Department Haryana



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

7 -
Proforma of Agreement

1. This agreement is made on _____ day of _____ month of _____ year between Sh./M/s _____ (hereinafter called the first party and DFCS&CA/DM/Manager of the FCI and concerned State Procurement Agency (hereinafter called second party).

2. The first party agrees to work as mandi labour contractor in respect of _____ mandi for doing various labour/local cartage works as per terms & conditions of the tender (enclosed).

3. That the second party has given approval of the rates given as under for which first party has agreed to work on such rates.

Part-I As per schedule rate

Part-II _____ %age above/below/at par of schedule rate

4. This agreement is valid upto **31.3.2023**.

5. In case any dispute arises between the contractor and the State Procurement Agency/FCI the matter will be referred to the Director/Director General Food and Supplies/M.D. of the concerned agency or his nominee for adjudicating the matter of dispute under the provisions of Arbitration Act, 1996 and his decision shall be binding on both the parties.

Executants

Party-Ist

Party-IIInd

Witness -----

1. _____

2. _____



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

- 8 -

FORMAT OF TECHNICAL BID (For Labour and Cartage Tender 2022-23)

Sr. No.	Particulars	
1.	<p>Detail of the duly self attested Certificate to be uploaded: (Yes/No)</p> <p>i) Certificate on proper stamp paper that the contractor/tenderer has not been blacklisted by any of the Government/Semi Government Department of the State & by FCI, and not connected to any blacklisted firm.</p> <p>ii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender or he/she may have agreement with any transport company/truck owners. If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3, L-4, L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. <u>with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ Rs 60,000/- per trucks of short no of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. The additional security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points.</u> The same will be applicable for all the tenderers. (As per terms and conditions).</p> <p>iii) Certified Partnership Deed in case of partnership concerns.</p> <p>iv) Solvency certificate issued by the banker.</p> <p>v) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.</p> <p>vi) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.</p> <p>vii) Letter from the bank regarding credit/limits enjoyed.</p> <p>viii) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of preceding last three financial years.</p> <p>ix) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value.</p> <p>x) Proof/Certificate of satisfactory work done during previous three years in the field of mandi labour and cartage work only from the concerned DFSC/DMs of the state procurement agencies & FCI having detail of volume of work done in the mandis.</p>	
2.	Detail of Earnest Money Deposit and for Labour and Transportation payment.	<p>RTGS... NO</p> <p>DATE....</p> <p>NAME OF BANK.....</p> <p>AMOUNT.....</p>
3	Whether the copies of the following documents duly signed at each page have been uploaded (write Yes or No)	
	i) Tender Documents and Terms & Conditions.	
	ii) Power of attorney to sign the tender documents.	



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

9

टैन्डर फार्म

श्रम ढुलाई व कारटेज कार्य हेतु

वर्ष 2022-23

टैन्डर नोटिस क्रमांक:

दिनांक

1. केन्द्र का नाम जिसके लिए टैन्डर दिया जाना है
2. धरोहर राशि
3. प्रतिभूति की राशि
4. टैन्डरदाता व पार्टी का नाम
5. पिता का नाम
6. वर्तमान पता
7. स्थाई पता (As per voter list/ration card/identity card/licence)
8. मोबाईल नम्बर: ई-मेल आईडी

Affix attested
Passport Size
Photograph of
tenderer

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टैन्डरदाता विभाग के कार्यों के लिए बलैक लिस्टिड नहीं है व ना ही किसी ब्लैकलिस्टिड फर्म से सम्बंध है ।

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें नियन्त्रक,

सेवा में

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें नियन्त्रक

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित टैन्डर नोटिस की सभी धाराओं का तथा उसके साथ सभी संलग्न दरों का भली भांति अध्ययन कर लिया है और मैं/हम उपरोक्त वर्णित केन्द्र पर उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए श्रम व ढुलाई का कार्य अनुबन्ध 'ए' भाग- II के कार्य निम्नलिखित टैन्डर दरों पर करने के लिए सहमत है/हूँ ।

1. प्रतिशत उपर
2. बेसिक दर
3. प्रतिशत कम दर

बैंक का नाम

आर टी जी एस

राशि

हस्ता 0 टैन्डरदाता

कार्यालय उपयोग के लिए

तकनीकी बोली में सफल हाने उपरांत टैन्डरदाता का टैन्डर फार्म निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में खोला गया

जि.प्र.

जि.प्र.

जि.प्र.

जि.खा.पू.नि. एवं उ.म0अ0(ना0)

पुलिस अधीक्षक

एफ.सी.आई

हैफेड

एच.डब्ल्यू.सी.

जि.प्र. कान्फैड

उपायुक्त/प्रतिनिधि उपायुक्त



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

/0 -

टैन्डर फार्म

श्रम ढुलाई व कारटेज कार्य हेतु

वर्ष 2022-23 टैन्डर नोटिस क्रमांक:

दिनांक

1. टैन्डरदाता व पार्टी का नाम
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थाई पता As per voter list/ration card/identity card/licenece
5. केन्द्र का नाम जिसके लिए टैन्डर दिया जाना है
6. धरोहर राशि
7. बैंक का नाम आर टी जी एस राशि
8. मोबाईल नं० ई०-मेल आई०डी०

Affix attested
Passport Size
Photograph of
tenderer

सेवा में

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें नियन्त्रक

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित टैन्डर नोटिस की सभी धाराओं का तथा उसके साथ सभी संलग्न दरों का भली भान्ति अध्ययन कर लिया है और मैं/हम उपरोक्त वर्णित केन्द्र पर उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए श्रम व ढुलाई का कार्य अनुबन्ध 'ए' भाग-॥ के कार्य निम्नलिखित टैन्डर दरों पर करने के लिए सहमत है/हूँ।

1. प्रतिशत उपर
2. बेसिक दर
3. प्रतिशत कम पर

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/है कि मैं/हम अथवा मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी/सोसाईटी किसी भी विभाग/एजेंसी के कार्यों के लिए ब्लैकलिस्टिड नहीं है व ना ही मेरा किसी ब्लैकलिस्टिड फर्म से सम्बंध है।

हस्ता० टैन्डरदाता

कार्यालय उपयोग के लिए

तकनीकी बोली में सफल होने उपरांत टैन्डरदाता का टैन्डर फार्म निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में खोला गया:-

जि.प्र. एफ.सी.आई	जि.प्र. हैफेड	जि.प्र. एच.डब्लयु.सी.	जि.खा.पू.नि. एवं उ.म०अ०(ना०) जि.प्र. कान्फैड	पुलिस अधीक्षक
---------------------	------------------	--------------------------	---	---------------

उपायुक्त/प्रतिनिधि उपायुक्त



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

— 11 —

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL, FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS HARYANA, CHANDIGARH

E-TENDER NOTICE FOR LABOUR AND CARTAGE FOR THE YEAR 2022-23

E-Tenders are invited from labour contractors other eligible entities for doing various labour and cartage operations of foodgrains/coarsegrains/oil seed/stock articles as shown in part-II of the Annexure "A" for all the mandis/godowns except in the godowns constructed/operated under FCI guarantee scheme falling in each district for the year **2022-23** in respect of State Procurement Agencies i.e. Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Department, Haryana State Co-operative Supply & Marketing Federation (Hafed), Haryana Warehousing Corporation (HWC) and Food Corporation of India (FCI). The tenders in respect of all the State Procurement Agencies and FCI shall be received by the concerned Deputy Commissioner/Tender Committee/DFSC:

Sr. No.	Name of District	Release/Calling of Tender up to 5.00 PM.	Opening of Technical Bid & Checking of documents up to 2:00 PM.	Opening of Financial Bid & negotiation & finalization.
1.	Ambala	08.03.2022	15.03.2022	As per decision of Distt. Tender Committee.
2.	Bhiwani	08.03.2022	15.03.2022	-do-
3.	Charkhi Dadri	08.03.2022	15.03.2022	-do-
4.	Faridabad	08.03.2022	15.03.2022	-do-
5.	Fatehabad	08.03.2022	15.03.2022	-do-
6.	Gurgaon	08.03.2022	15.03.2022	-do-
7.	Hisar	08.03.2022	15.03.2022	-do-
8.	Jhajjar	08.03.2022	15.03.2022	-do-
9.	Jind	08.03.2022	15.03.2022	-do-
10.	Kaithal	08.03.2022	15.03.2022	-do-
11.	Karnal	08.03.2022	15.03.2022	-do-
12.	Kurukshetra	08.03.2022	15.03.2022	-do-
13.	Mewat	08.03.2022	15.03.2022	-do-
14.	Narnaul	08.03.2022	15.03.2022	-do-
15.	Palwal	08.03.2022	15.03.2022	-do-
16.	Panchkula	08.03.2022	15.03.2022	-do-
17.	Panipat	08.03.2022	15.03.2022	-do-
18.	Rewari	08.03.2022	15.03.2022	-do-



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

- 12 -

19.	Rohtak	08.03.2022	15.03.2022	-do-
20.	Sirsa	08.03.2022	15.03.2022	-do-
21.	Sonepat	08.03.2022	15.03.2022	-do-
22.	Yamuna Nagar	08.03.2022	15.03.2022	-do-

1. The Date, time and venue for receiving/opening/last date of applying (closing date of tenders shall be fixed by the concerned Deputy Commissioner/ Tender Committee as per details given in the tender notice.
(ii) Subject to the consent approval of the Distt. Tender Committee if required re-tendering shall be fixed accordingly.
2. Tender forms and detail terms and conditions can also be downloaded from the website of this department i.e. <http://haryanafood.nic.in>.
3. In case of any enquiry/problem, the concerned Distt. Food and Supplies Controller for Food and Supplies Department/Distt. Manager of the respected procurement agency may be contacted.
4. The procurement figures of Wheat, Paddy, foodgrains, pulses, mustard, bajra, coarsegrain and other articles purchased during Rabi & Kharif Marketing Season for the year **2021-22**(if required) can be obtained from the concerned Agency on any working day.
5. The District Tender Committee reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. After the final acceptance of the tender by the tender committee, no request for further increase of rate for any operation shall be entertained.

Meenu
7/3/22

Deputy Director
for General Director Food Civil Supplies and
Consumer Affairs Department Haryana



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
**Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.**

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

13-

I/we hereby state that:-

1. I/we have thoroughly read all the schedules, appendices, and annexures to the tender documents, terms & conditions carefully.
2. Our offer is as per Terms and Conditions given in the tender document.

Signature-----

Seal/Stamp

Full Name of the authorized signatory (mandatory)-----

Designation of the signatory (mandatory)-----

Contact No. of signatory (mandatory)-----

E-Mail ID of signatory-----



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
**Directorate of Food Civil Supplies &
Consumer Affairs Department**
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

193

To

- 14-
1. The Executive Director, Food Corporation of India, A-2A-2B, Sector 24 Noida, Uttar Pradesh.
 2. The General Manager Food Corporation of India, Haryana Region, Panchkula.
 3. Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.
 4. Chief Administrator HSAMB, Sector 6, Panchkula.
 5. Managing Director, Hafed Sector-5, Panchkula.
 6. Managing Director, HSWC Sector-2, Panchkula.

Memo No. SOMP-1-2021/14788

Dated 23/07/21

Subject:- Minutes of meeting of State Level Committee(SLC) held on 13.07.2021 under the Chairmanship of Worthy ACS, FCS&CA regarding revision of SoR of Labour and Cartage rates.

I am directed to invite your kind attention on the subject cited above and the copy of minutes of meeting is hereby attached for further necessary action in this regard.

Deputy Director
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs,
Haryana, Chandigarh

Endst No. SOMP-2021/14789

Dated, the Chandigarh 23/07/21

A copy of the above is forwarded to the Director, Ministry of Consumer Affairs, Food & PD, Department of Food & PD, Govt. of India, Krishi Bhawan New Delhi w.r.t. letter no. 191(1)/2019- FC A/cs part file-I dated 24.02.2021 for information please.

Deputy Director
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs,
Haryana, Chandigarh

CC

1. SS/ACS, FCS & CA for kind information of Worthy ACS, FCS&CA.
2. PS/DFS for kind information of Worthy DFS.
3. JCFA(HQ) w.r.t their letter U.O.No.1(1) 2020-21/comp.-II/12053 dated 21.06.2021 for necessary action.
4. Computer Cell for uploading on department website.

15 -

195-

Subject:- Minutes of the Meeting held on 13.07.2021 under the chairmanship of Sh. Anurag Rastogi, IAS, Additional Chief Secretary, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana regarding revision of SoR of Labour and Cartage rates.

A meeting was held on 13.07.2021 under the Chairmanship of, Additional Chief Secretary, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana regarding revision of SoR of Labour and Cartage rates.

List of the Participants is as under:-

1. Sh. Om Parkash, General Manager, Food Corporation of India.
2. Sh. Chander Shekhar Khare, Director, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department.
Sh. Ashok Kumar Sharma, Managing Director, Haryana Warehouse Corporation.
Sh. Harshit Singh, General Manager (Proc), Food Corporation of India, Zonal Office, Noida (Through Video Call)
5. Dr. Anita Kharub, Deputy Director, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department.
6. Sh. R.P Sahni, Chief General Manager, HAFED.
7. Sh. Manjeev Kumar Goyal, Dy General Manager, Food Corporation of India.
8. Sh. Anuj Tyagi, General Manager (P&W), HAFED.
9. Sh. A.K Ahuja, General Manager (P&W), HAFED.
10. Sh. Sunil Sharma, CMEO, HASMB.

At the outset Director FCS&CA welcomed the worthy Chair and other participants and put up the agenda for the meeting. He apprised about the need revision of SoR rates of Labour and Cartage which were earlier revised in 2011-12. After detailed discussion with the participants. It has been decided that SoR rates may be modified and revised on the pattern of FCI, Haryana. New rates are to be fixed as under:-

SCHEDULE OF RATES AND SERVICES FOR LABOUR/HANDLING AND CARTAGE CONTRACTORS

PART-A (NON-PREMIUM OPERATIONS)

The contractor or casual labour, as the case may be, has to perform the work on the basic rates, without any premium, for the following operations:

- 196 -

- 2 - 16 -

PURCHASE CENTRE OPERATIONS

OPERATIONS TO BE PERFORMED BY ARHTIAS/COMMISSION AGENTS.

Sr. No.	Particulars	
1	Unloading	As per rates already fixed by SLC and notified by Haryana State Agricultural and Marketing Board.
2	Power operated cleaning (per Sieve)	
3	Weighing & filling	
4	Stitching Manual/ Machine including sutli.	
5	Loading	

PART-B (PREMIUM OPERATIONS)

1. LABOUR CHARGES FOR LOADING/UNLOADING OF FOODGRAINS

S.No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing >40 upto 50 kg.
1.1	Unloading of foodgrains from wagons/ trucks/any other transport vehicles and directly loading on trucks/ wagons /any other transport vehicles	Rs 52	Rs. 76.00
1.2	Unloading of foodgrains from trucks/ any other transport vehicles including stacking in open/covered storage points	Rs. 78.00	Rs. 112.00
a.	Conventional Stacking in Shed/ Platform / Ground/ Up to 10 high		
b.	Upto 16 high (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 87.00	Rs. 123.00
c.	Upto 20 high (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 95.00	Rs. 137.00
d.	Beyond 20 high (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 103.00	Rs. 150.00
2.	Breaking the Stacks and Loading of foodgrains into wagons/trucks/any other vehicles	Rs.52.00	Rs.76.00

2. LABOUR CHARGES FOR LOADING/UNLOADING OF STOCK ARTICLES

S.No.	Name of Operation	Rate per Stock Article
1 a	Unloading /Stacking /Removing/loading of gunny(jute)/ bales at Railway Station/godown/purchase centre (per operation)	Rs. 7.10
b.	Unloading /Stacking	Rs. 7.10

	/Removing/loading of tarpaulins/fumigation covers at godown/purchase centre (per operation)	
2.	Unloading/ Stacking /Removing/loading of HDPE at Railway Station/godown/purchase center(per operation)	Rs. 4.50
3.	Loading /unloading of wooden crates from mandi/godowns(per operation)	Rs. 1.20

3. PRESERVATION AND MAINTENANCE OF ITEMS

S.No.	Name of Operation	Rate
1.	Coverage/removing of stocks with polythene cover/tarpaulins.	Rs. 8.00/- each without tender premium .
2.	Mud plastering of polythene covers for fumigation including cost of material i.e. clay, mud, gobri and bhusa, etc. (Maximum 4 a year) and subject to the verification of AFSSO	Rs. 20/- each operation (payment of this operation will be made to the person who actually performed the duty after verification by the AFSSO himself
3.	Opening and closing of doors & windows at the time of fumigation including cost of material i.e. clay, mud, gobri & bhusa etc.	1. Per door Rs. 4.20 2. Per window Rs. 2.80 3. Per ventilator Rs. 2.80

4. UPGRADATION/REPLACEMENT

S.No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 50 kg.
1.	For carrying the Food Grains Bags from the Stacks or anywhere in the Godown premises, cutting open the mouth of bags, pouring out the contents on floor/tarpaulins, making heaps, mixing or blending thoroughly to present desire quality, filling the loose grains into empty gunnies upto a prescribed weight, stitching the bags and then stacking the bags in the same or another godown. Conventional Stacking in Shed/ Platform / Ground/ Up to 10 high	Rs 110.00	Rs. 155. 00
a.			
b.	Upto 16 high (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 121.00	Rs. 175.00
c.	Upto 20 high (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 131.00	Rs. 186.00
d.	Beyond 20 high (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 141.00	Rs. 198.00

198

18

2.	Changing of bags (reconditioning the bags) including paltai into other bag, opening sewing and weighment.		
a.	Conventional Stacking in Shed/ Platform / Ground/ Up to 10 high	Rs 95.00	Rs.137.00
b.	Upto 16 high (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 110.00	Rs. 155.00
c.	Upto 20 high (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 121.00	Rs. 175.00
d.	Beyond 20 high (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 132.00	Rs. 195.00

5. STANDARDIZATION

S.No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing >40 upto 50 kg.
1.	For carrying the Foodgrains bags from the stacks or anywhere in the Godown premises, cutting open the mouth of bags, placing on scale and weighment, sewing after pura-karai (bringing to standard weight) when rebagging is not involved and stacking.		
a.	Conventional Stacking in Shed/ Platform / Ground/ Up to 10 high	Rs 95.00	Rs 137.00
b.	Upto 16 high (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 110.00	Rs. 155.00
c.	Upto 20 high (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 121.00	Rs. 175.00
d.	Beyond 20 high (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 132.00	Rs. 195.00

6. PHYSICAL VERIFICATION

S.No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing >40 upto 50 kg.
1.	Breaking/Removing out of godown weighing on platform/beam scale and restacking in godown after physical verification of stock.		
a.		Rs 87.00	Rs 123.00

519- 199

	Conventional Stacking in Shed/ Platform / Ground/ Up to 10 high		
b.	Upto 16 high (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 99.00	Rs. 144.00
c.	Upto 20 high (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 110.00	Rs. 155.00
d.	Beyond 20 high (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 120.00	Rs. 166.00

CARTAGE CHARGES:

S. No.	Distance from loading point to destination point.	Rate per Quintal (in Rupees)
1	0 to 8 K.M	12.50 *

*Note: * As fixed by SLC vide Memo No. SOMP-1-2020/14209 dt 20.08.2020*

The break-up of 0-8 kilometers as per above rates is as under:-

S. No.	Slab	Distance from loading point to destination point.	Rate per Quintal (in Rupees)
1.	Slab-1	>0 < 1 K.M	4.50
2.	Slab-2	>1 < 2 K.M	5.50
3.	Slab-3	>2 < 3 K.M	6.50
4.	Slab-4	>3 < 4 K.M	7.70
5.	Slab-5	>4 < 5 K.M	8.90
6.	Slab-6	>5 < 6 K.M	10.10
7.	Slab-7	>6 < 7 K.M	11.30 *
8.	Slab-8	>7 upto 8 K.M	12.50

The above rates shall be applicable from 01.04.2022 .

Further, it has also been decided by SLC that in future the tenders of MLC and MTC may be called jointly by the District Tender Committee headed by Deputy Commissioners for all procuring agencies including FCI w.e.f. RMS 2022-2023:

The meeting ended with a vote of thanks.